

प्रार्थी के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, यदि अपीलाधीन आदेश की पालना नहीं रोकी गई तो अपीलाधीन आदेश की आड में 1/2 हिस्से की जगह अप्रार्थीगण सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा देंगे। जिससे अपीलान्त का अपूर्णनीय हानि होगी तथा पक्षकारों में विवाद बढ़ेगा। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित रख जाने व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में आर.आर.डी. 2004 पेज 727, आर.आर.डी. 1998 पेज 553 पेश की।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.2.2018 का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर तहसीलदार, शिव को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित भूमि खेत खसरा संख्या 226,774/213 व 781/216 मौजा शिव के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर निर्णित होकर मूल पत्रावली के संलग्न हो।